

कांग्रेस का दोहरा चरित्र

देश की आजादी के लिये स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जिस मंच का सन् 1947 तक उपयोग किया 1885 से सन् 1947 वह कांग्रेस थी। लेकिन जैसे-जैसे क्रान्तिकारियों के तेजस्वी नेतृत्व में स्वाधीनता निकट दिखाई दी, कांग्रेस का नेतृत्व स्वार्थी और संकीर्ण सोच के लोगों के पास चला गया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के स्थान पर पट्टाभि सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थान पर पं. जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना आदि न जाने कितनी गलतियाँ बराबर हुईं और आज भी पूरा भारत इन गलतियों की सजा भुगत रहा है। आज भी कांग्रेस के दोहरे चरित्र एवं मनमानेपन के कारण पूरा देश आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद तथा भ्रष्टाचार की चपेट में है। पंजाब का आतंकवाद रहा हो अथवा असम का उग्रवाद या दक्षिण में लिट्टे का अलगाववाद, सभी कांग्रेस नेतृत्व की देन हैं। कौन नहीं जानता कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने असम में उल्फा से राजनीतिक समर्थन हासिल किया। बिहार में एम.सी.सी. तथा आन्ध्र प्रदेश में पीड.ब्लू.जी. से भी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने समर्थन हासिल किया। जब आतंकवादियों, उग्रवादियों तथा विघटनकारी संगठनों से समर्थन लिया जायेगा तो फिर उनकी समाज विरोधी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता है। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र एक बार पुनः तब प्रदर्शित हुआ है जब पिछले सप्ताह उसके नेतृत्व की केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने उड़ीसा और कर्नाटक की सरकार को धारा.355 के तहत नोटिस जारी किया। किसी भी राज्य में असाधारण परिस्थितियों में कानून व्यवस्था की चरमराई स्थिति में यह नोटिस ,धारा.356 की कार्रवाई, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, के पहले की कार्रवाई है। क्या कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर यू.ए.पी. सरकार का यह कार्य न्याय-संगत एवं उचित माना जायेगा? अगर कांग्रेस नेतृत्व की शह पर केन्द्र उड़ीसा और कर्नाटक की घटनाओं के लिये दोनों राज्य सरकारों को

नोटिस जारी करता है तो आखिर इस प्रकार की नोटिस क्यों असम, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड तथा आन्ध्रप्रदेश की सरकार को जारी नहीं की गई ? उड़ीसा और कर्नाटक के अन्दर जो कुछ हुआ या हो रहा है वह हिन्दुओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानी जानी चाहिए। जिस प्रकार से उड़ीसा के अन्दर चर्च द्वारा प्रायोजित उग्रवादियों ने वरिष्ठ सन्त स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती की शिष्यों सहित हत्या की, अगर इस पर भी हिन्दू चुप रहता तो इससे बड़ी कायरता और कोई नहीं होती। क्योंकि स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती ने उड़ीसा के वनवासी क्षेत्रों में जो सकारात्मक कार्य करके भटके हुए वनवासी जनजातीय समूहों को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया था, वह अविस्मरणीय एवं सराहनीय है। इसी कारण समाज विरोधी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त संगठन तथा चर्च को यह सब पसन्द नहीं आया। लगातार स्वामी जी को धमकियाँ दी गईं। उन पर पूर्व में हमला भी हुआ था, लेकिन स्वामी जी को सुरक्षा नहीं दी गई। यही स्थिति कर्नाटक में भी है। चर्च की भूमिका पूरे देश के अन्दर लगातार अलगाववाद को फैलाने की रही है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों का अलगाववाद हो अथवा छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आदि तमाम राज्यों में चर्च लोभ, लालच तथा जबरन मतान्तरण के द्वारा अलगाववाद को हवा दे रहा है। इसी मतान्तरण का दुष्परिणाम है कि आज पूर्वोत्तर भारत समेत देश के तमाम राज्य इस आग से झुलस रहे हैं। केन्द्र सरकार इस अलगाववाद को तो नहीं रोकती है। हिन्दू विरोधी गतिविधियों को सेकुलरिज्म के नाम पर नजरअन्दाज किया जाता है जिसकी स्वाभाविक परिणति आज उड़ीसा तथा कर्नाटक के हिन्दुओं के आक्रोश के रूप में देखने को मिल रही है। हिन्दुओं के स्वाभाविक आक्रोश पर तो केन्द्र सरकार उड़ीसा और कर्नाटक सरकारों को धारा-के तहत नोटिस जारी करती है लेकिन असम में कांग्रेस की सरकार 355-अ के संरक्षण में उल्फा द्वारा दो वर्षों में दो सौ से अधिक हिन्दी भाषी नागरिकों की हत्या करने पर तथा दर्जनों बस्तियों में आग लगा देने पर तो असम सरकार को

कोई नोटिस जारी नहीं हुई। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे द्वारा कांग्रेस की शह पर उत्तर भारतीय नागरिकों की हत्याएँ, लूट-पाट और जबरन मारपीट का जो नग्न तांडव जारी है उस पर महाराष्ट्र की सरकार को नोटिस जारी नहीं होती है। जम्मू-कश्मीर के अन्दर गुलाम नबी आजाद सरकार और उससे पहले कांग्रेस के समर्थन से चली मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार के समय हिन्दुओं, बौद्धों तथा सिखों के साथ जो कुछ हुआ, उ .प्र.और बिहार के मजदूरों पर जो अत्याचार हुआ तथा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुद्दे पर सरकार का जो रवैया था, अफजल जैसे देशद्रोही के समर्थन में मुख्यमंत्री द्वारा खुलेआम बयानबाजी की गई तब भी वहाँ की सरकार को नोटिस जारी नहीं हुई। कांग्रेस और यू.ए.पी. सरकार का यह दोहरा चरित्र इस देश की जनता को जानना होगा। यही दोहरा चरित्र देश के विभाजन का कारण बना और यही दोहरा चरित्र वर्तमान आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद तथा भ्रष्टाचार का कारण है। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिये कांग्रेस नेतृत्व जो कुछ कर रहा है वह राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिये खतरनाक ही साबित होगा।